

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

क्रमांक/ <sup>647</sup> /738/2020-21/26-2


भोपाल, दिनांक 04.03.2021

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना एवं कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समयावधि इस वजह से दी गई है जिससे की समय रहते ऐसे प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में किया जाकर हितग्राही को योजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र प्रदाय किया जा सके। लेकिन इस समयावधि का अर्थ यह नहीं है कि पात्र हितग्राही को पात्रता के निर्धारित मापदण्ड में आने के बाद भी मात्र समयावधि के उल्लंघन की वजह से योजना के लाभ से वंचित रखा जायें।

अतः ऐसे जो भी प्रकरण जिसमें निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी आवेदन प्राप्त होता है, उन सभी प्रकरणों में यदि देरी का कारण युक्तिसंगत है तो ऐसे प्रकरण में पात्रतानुसार हितग्राही को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया जायें। सिर्फ इस वजह से कि हितग्राही ने समय पर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है उसको इस आधार पर अपात्र मान कर योजना के लाभ से वंचित न रखा जायें।

ऐसे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करने की कार्यवाही संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक प्रकरणों में कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे। ऐसे प्रकरणों में आयुक्त / संचालक अथवा शासन की पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के शेष प्रावधान पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

  
(प्रतीक हजेला)

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक :- 04.03.2021

पृ.क्रमांक/ <sup>648</sup> /738/2020-21/26-2  
प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल।

//2//

5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संयुक्त / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

 04/02/2024

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग